केंद्र से डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए नियम बनाने की मांग

- मांगों को लेकर जल्द ही केंद्रीय मंत्री से मिलने पर बनी सहमति

आज समाज नेटवर्क

नई दिल्ली/गुरुग्राम। चिटफंड कंपनियों के कारण धुमिल हो रही अपनी छवि से चिंतित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां अब चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसने के लिए खुद आगे आने लगी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की ऐसोसिएशन एडीएसईआई (एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ऑफ इंडिया) ने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लेकर केंद्र सरकार से नियम बनाने की मांग की है ताकि चिटफंड कंपनियों पर शिकंजा कसा जा सके। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की ऐसोसिएशन एडीएसइआई का मानना है कि रूल्स बनने के बाद रोजगार सर्जन,आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना एवं वोकल फॉर लोकल के उद्देश्य से कार्य कर रही डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए काम करना और भी आसान हो सकेगा। रविवार को रोहिणी के एक फाइव स्टार होटल में आयोजित डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के समिट में एकजुटता से यह निर्णय लिया गया कि इस संबंध में जल्दी ही एडीएसईआई का एक प्रतिनिधि मंडल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों और अधिकारियों से मिलेगा। समिट में देश भर की लगभग 50 से अधिक डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के डायरेक्टर्स ने हिस्सा लिया और भविष्य की योजनाओं और इस व्यवसाय से जुड़ी कंपनियों के सामने आ रही समस्याओं एवं उनके निदान पर विस्तृत चर्चा की। एसोसिएशन के सचिव एवं केंद्रीय खाद्य वितरण एवं उपभोक्ता मंत्रालय के पूर्व सचिव हेम पांडे ने यहां आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को सच करने में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की भूमिका को महत्वपूर्ण माना। इस ग्रांड समिट में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए भाजपा नेता उत्तरी पूर्वी दिल्ली से सांसद एवं दिल्ली भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा कि निश्चित ही कुछ चिटफंड कंपनियों के कारण ईमानदारी से कार्य कर रही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जुड़े व्यवसायियों को परेशानी उठानी पड़ रही है। मनोज तिवारी ने कहा कि जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है उसके बाद से इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन शुरू हो चुके है।